हिंदी सांध्य दैनिक

भवानी टाईम्स

प्रधान संपादक : चंद्रकांत खंडेलवाल, 9422831140

RNI Reg.NO.39851/1981

E-mail : bhawanitimes@gmail.com

वर्ष : 46 अंक : 17 गोंदिया, गुरूवार दि. 18 जुन 2026 पृष्ठ : 04 मूल्य : 1.10 रू Post Redg.NPMFL/27/2024-2026

नेटवर्क समस्या से कामकाज में बाधा

देवरी : ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में इन दिनों स्लो इंटरनेट स्पीड व नेटवर्क की गंभीर समस्या बन गई है. पिछले अनेक दिनों से कवरेज नहीं मिल पाने के कारण तहसील के मोबाइल धारक पूरी तरह त्रस्त हो गए हैं. रिचार्ज करने के बाद माह में 4-5 दिन बराबर नेट चलता है लेकिन इसके बाद ज्यों की त्यों स्थिति बनी रहती है. दिन भर में कुछ ही समय नेट चलता है व बातचीत होती है. उपभोक्ताओं की ओर से 3 माह के लिए 800 से 900 रु. अदा करने पर कवरेज व बराबर नेट नहीं मिलता और बेवजह रिचार्ज के पैसे खत्म हो जाते हैं. इसे सुधारने की मांग की जा रही है.

संक्षिप्त

जंगली सुअर व बंदरों से परेशानी

गोरेगांव : आए दिन ग्रामीण क्षेत्र के अनेक गांवों में बंदरों व सुअरों का आतंक बढ़ने से खेती करना मुश्किल होते जा रहा है. जंगली जानवर किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं. गांवों में बंदरों व जंगली सुअरों का आतंक काफी बढ़ गया है. जानवर किसानों द्वारा उगाई गई सब्जी और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. बंदर कई बार घर और घर की छतों पर आकर उत्पात मचा रहे हैं. ग्रामीण जहां बाजार से महंगा बीज खरीद कर सब्जी उगाते हैं, लेकिन ज्यों ही सब्जी तैयार होती है सुअर और बंदर उसे नष्ट कर देते हैं. ऐसे में कई बार उन्हें बीज की लागत भी नहीं मिल पाती है.

छापे में 2 घरों से शराब जब्त की

गोंदिया : शहर व गंगाझरी पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर देशी शराब जब्त की है. पहली कार्रवाई शहर थाना क्षेत्र के संजय नगर में की गई. इस दौरान पुलिस ने विकास विजय गडपायले (28) के घर पर छापा मारकर प्लास्टिक की डिब्बे में रखी करीब 5 लीटर देशी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1,000 रु. बताई गई है. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर से अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहा है. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब जब्त की गई तथा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई गंगाझरी थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदेखारी में की गई. यहां पुलिस ने दीपक कपुरचंद वरकड़े (32) के घर पर छापा मारकर 5 लीटर देशी शराब जब्त की. गंगाझरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

३ मकानों पर छापा देशी शराब जब्त

गोंदिया : चिचगड़, दवनीवाड़ा और रामनगर पुलिस ने तीन घरों में छापा मारकर देशी शराब को जब्त किया. चिचगड़ थाने के तहत सिंधीबिरी में जगदीश डोमा करंडे (34) के घर में पुलिस ने छापा मारकर देशी शराब से भरी 10 बोतलों को जब्त किया. उक्त आरोपी ने अपने घर में पॉलिथीन में अवैध रूप से देशी शराब को छुपाकर रखा था. दवनीवाड़ा थाने के तहत ग्राम खड़बंदा में तीर्थराज भाऊलाल भुजाडे (52) के घर में पुलिस ने छापा मारकर 10 लीटर देशी शराब को जब्त किया. यह कार्रवाई हवलदार राजेश दमाहे ने की. रामनगर थाने के तहत गड्डाटोली में पुलिस ने रुखसाना फरीद खान पठान (60) के घर से 8 लीटर देशी शराब को जब्त किया.

जमीन विवाद में भाई की कुल्हाडी से हत्या

आरोपी भाई को किया गिरफ्तार

संवाददाता / गोंदिया

अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम परसटोला में बुधवार की सुबह जमीन के विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी. इस मामले में अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है. मृतक का नाम परसटोला निवासी मोहन मंगरू कवडो (47) व आरोपी का नाम नारायण मंगरू कवडो (44) बताया गया है. जानकारी के अनुसार, अर्जुनी मोरगांव तहसील के परसटोला निवासी मृतक मोहन मंगरू कवड़ो (47) और आरोपी नारायण मंगरु कवड़ो (44) आपस में सगे भाई हैं. उनके पिता ने उनके बीच खेत का बंटवारा कर दिया था. लेकिन क्योंकि मृतक मोहन कवड़ो अपने पिता की देखभाल करता था इसलिए वह अपने पिता के हिस्से की खेती करता था.

इसी बीच घटना वाले दिन 17 जून की सुबह करीब 10 बजे जब मोहन कवड़ो अपनी पत्नी के साथ खेत पर गया तो आरोपी नारायण कवड़ो वहां आ गया. दोनों के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि मुझे मेरे पिता के हिस्से की मेढ़ दे दी जाए. बहस जब मारपीट में बदल गई तो आरोपी ने गुस्से में आकर मोहन कवड़ो पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पत्नी कविता मोहन कवड़ो (40) ने केशोरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसकी शिकायत के आधार पर, केशोरी थाने में मामला दर्ज किया तथा तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नारायण कवडो को हिरासत में ले लिया. जांच पुलिस निरीक्षक मंगेश काले के मार्गदर्शन में चल रही है.

फांसी लगाकर दी जान

गोंदिया : गोरेगांव थाने के तहत सोनी निवासी संतोष हीरालाल मौजे (39) ने गांव जंगल में स्थित तालाब के पास पेड़ को रस्सी की मदद से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. भुमेश्वर शोभीलाल मौजे (41) की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है.

किडंगीपार में ट्रेन से गिरकर युवक घायल

गोंदिया : आमगांव तहसील अंतर्गत ग्राम किडंगीपार के रेलवे क्रॉसिंग पर चलती ट्रेन से एक युवक गिर गया. जिसमें वह घायल हो गया. घायल युवक का नाम तुलाराम रतनलाल टंडन (32) बताया गया है. घायल युवक को आमगांव के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया. हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के उपचार के लिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में रेफर किया गया.

किसानों को २४ घंटे बिजली उपलब्ध हो

संवाददाता / तिरोड़ा

8 घंटे की जगह 24 घंटे बिजली की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से तिरोड़ा शहर में 'भव्य किसान मोर्चा' का आयोजन किया गया. प्रहार के जिला अध्यक्ष महेंद्र भांडारकर के नेतृत्व में सुकड़ी नाका से लेकर तहसील कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया और ऊर्जा मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया. गोंदिया जिले को धान का भंडार कहा जाता है.

चावल की खेती में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है. भौगोलिक दृष्टि से 8 घंटे बिजली आपूर्ति के साथ चावल की खेती करना संभव नहीं है. इसलिए इस समय कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली देने और कृषि के लिए सोलर कनेक्शन की शर्त को रद्द कर पहले की तरह सीधे बिजली कनेक्शन देने की प्रमुख मांग की गई.

इस मोर्चे में प्रहार जनशक्ति के साथ विभिन्न संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए थे. इस अवसर पर शिवसेना शिंदे गुट के महिला जिला प्रमुख ज्योति लिल्हारे, ओबीसी संगठन के खुशाल शेंडे, गांगला के सरपंच बुद्धे, मुरमाड़ी के उपसरपंच राजू मेहर, बयवाड़ा के उपसरपंच महेंद्र भुरे, मुरपार के पूर्व सरपंच राजेंद्र फाये, मिथुन वासनिक, शुभम वासनिक, उरकुडा उके, गिरधारी रहांगडाले साथ ही नवेझरी, सितेपार, कुल्पा, मुरपार, सिल्ली, गांगला, बयवाड़ा के किसान उपस्थित थे.

अब तक नहीं हुई प्री मानसून की दस्तक, पेयजल संकट गहराया

गर्मी व उमस से जनजीवन हुआ प्रभावित

संवाददाता / गोंदिया

प्री-मानसून की दस्तक अब तक नही हो पाई है. वर्तमान में भी गर्मी लोगों की सहन शक्ति की लगातार परीक्षा ले रही है. इधर जितनी लंबी बारिश खीचेंगी उतना ही पेयजल संकट गहराता जाएगा. अब सभी लोगों को रिमझिम व झमाझम बारिश के दौर का इंतजार है. जून माह चल रहा है और अभी तक अप्रैल व मई वाली गर्मी का ही अहसास हो रहा है.

इधर आसमान पर हलके बादल भी छाए रहते हैं. इसके चलते सूर्यदेव लुकाछिपी भी करते हैं. वर्तमान में गर्मी सितम ढा रही है. उमस से हर कोई व्याकुल है. दोपहर के समय आसमान से बरस रही आग के सामने सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है. सूरज की तपन के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है. कुल मिलाकर तेज गर्मी की वजह से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है. दिन में सड़कों पर दोपहिया वाहन चालकों को सड़क किनारे पेड़ की छांव में गर्मी से बचने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है.

बढ़े हुए तापमान के कारण लोग सुबह से ही गर्मी से बेहाल हो उठते हैं. दिन के समय हालत ऐसी हो जाते है कि कूलर, पंखे चलाकर घरों में आराम करने वाले लोग भी उमस से बेहाल हो जाते हैं. दोपहर के समय तो कम ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं. गर्मी से लोग पसीना-पसीना हो रहे हैं. दिन भर की गर्मी व उमस से परेशान लोग शाम को प्राकृतिक वातावरण में कुछ सुकून पाते हैं.

पंप-पैनल ठीक हुआ तो अब बिजली बिल नहीं भरने से ४८ गांवों के नल बंद

१४-१५ को तकनीकी खराबी से पानी नहीं मिला

संवाददाता / गोंदिया

आमगांव - सालेकसा तहसील के 48 गांवों - कस्बों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने वाली बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पंप व पैनल में खराबी आ जाने के कारण रविवार, 14 जून को सभी गांवों की जलापूर्ति बंद हो गई थी। सोमवार, 15 जून को मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद 16, जून से सभी गांवों में सुचारू जलापूर्ति किए जाने की जानकारी विभाग की ओर से दी गई थी।

लेकिन इसी बीच 15 जून की शाम 6.30 बजे जिला परिषद जलापूर्ति विभाग की ओर से विद्युत विभाग के बकाया बिल की राशि नहीं भरने भरने के कारण योजना की विद्युत आपूर्ति खंडित कर दी गई। जिसके कारण सभी गांवों की जलापूर्ति फिर बंद हो गई है। पता चला है कि विद्युत विभाग का लगभग 48 लाख रुपए का बिल जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर बकाया है।

यह बकाया विद्युत बिल भरे जाने के बाद ही शुरू होने की जानकारी मिली है। इसमें कितना समय लगेगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता। अर्थात अब बकाया बिजली बिल के भरे जाने तक 48 गांवों के 50 हजार से अधिक नागरिकों को भरी गर्मी के इस मौसम में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा।

३ हजार गर्भवती माताओं की जांच

संवाददाता / गोंदिया

भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' ने 9 जून को सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस दशक के अवसर पर 'सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माता, सशक्त भारत' की संकल्पना के तहत जिले में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया. इसमें एक ही दिन में 3 हजार 247 गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच की गई तथा 35 उच्च जोखिम वाली माताओं का इलाज किया गया.

इस विशेष दिन के अवसर पर गोंदिया मंडल के स्वास्थ्य उपसंचालक डा. शंभरकर ने गोंदिया में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की गहन समीक्षा की. जिला शल्य चिकित्सक डा. पुरूषोत्तम पटले ने स्वयं रजेगांव के ग्रामीण अस्पताल का दौरा किया. शिविर में गर्भवती माताओं की नियमित प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की गई.

उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए विशेष रेफरल सेवाएं प्रदान की गईं. इस अवसर पर डा. अनुराधा मुंढे, डा. पलाश गणवीर, डा. सुवर्णा हुबेकर, डा. खंडेलवाल ने उपस्थित महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आहार, आराम और खतरे के लक्षणों पर मार्गदर्शन दिया. साथ ही विभिन्न शिविरों से 35 उच्च जोखिम वाली माताओं की पहचान कर उनका इलाज किया गया. इस विशेष अभियान की सफलता के लिए आरएमओ डा. बी.डी. जायस्वाल, डा. सचिन उईके, डा. गुरुप्रसाद खोब्रागड़े, जिला मातृ शिशु देखभाल अधिकारी डा. रोशन राऊत सहित सभी चिकित्सा अधीक्षक और स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ ने सहयोग किया.

तंबाकू खाने वाले २१ लोगों पर कार्रवाई

प्रशासनिक कार्यालयों में धूम्रपान प्रतिबंध की हो रही अनदेखी

संवाददाता / गोंदिया

सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू और तंबाकूजन्य उत्पादों को रखना और सेवन करना प्रतिबंधित है. सोमवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत केटीएस जिला सामान्य अस्पताल ने प्रशासनिक इमारत के कार्यालय में धूम्रपान रोकने के लिए एक अभियान चलाया. इस मौके पर 21 लोगों को दंडित किया गया और 3,550 रु. का जुर्माना वसूला गया.

जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से टीमों का गठन किया गया है. सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों को रखना और उनका सेवन करना प्रतिबंधित है. इसी के तहत जिलाधीश मंगेश गोंदावले ने सभी सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने का आदेश दिया. जिले के सभी सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है.

जिला शल्य चिकित्सक डा. पुरूषोत्तम पटले के मार्गदर्शन में जयस्तंभ चौक स्थित प्रशासनिक इमारत स्थित कार्यालय में विभिन्न विभागों में छापेमारी की गई और 21 कर्मचारी व लोगों पर 3550 रु. का जुर्माना लगाया गया. यह कार्रवाई तहसीलदार समशेर पठान, जिला शल्य चिकित्सक डा. पुरूषोत्तम पटले के मार्गदर्शन में जिला सलाहकार डा. ज्योति राठौड़, मनोवैज्ञानिक सुरेखा आजाद मेश्राम, सामाजिक कार्यकर्ता संध्या शंभरकर, दंत तकनीशियन यश जायस्वाल, दंत सहायक विवेकानंद कोरे के साथ पुलिस विभाग के दिगंबर झिंजुर्डे व सिपाही राठौड़ ने की.

द्वारका नगर के नागरिकों ने नप प्रशासन को घेरा

जलभराव से निपटने नालियों का निर्माण करें

संवाददाता / आमगांव

शहर के द्वारका जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने एक बार फिर नप प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है.

द्वारका नगर क्षेत्र के नागरिकों ने मुख्याधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि, मानसून के दौरान, आपले सरकार पोर्टल पर शिकायत के माध्यम से जमा हुए पानी की निकासी के लिए नाली के निर्माण की मांग की गई थी. इस संबंध में, नप प्रशासन ने नागपुर मंडल के संयुक्त आयुक्त, नप प्रशासन को पत्र भेजकर संबंधित स्थानों पर पानी की निकासी के लिए एक अस्थायी कच्ची नाली बनाने का अनुरोध किया था. लेकिन यहां के निवासियों के अनुसार क्षेत्र की वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है.

कच्ची नाली का निर्माण नहीं: आज तक किसी कच्ची नाली का निर्माण नहीं हुआ है. नागरिकों का दावा है कि पक्की नाली के निर्माण से संबंधित कोई योजना या प्रस्ताव नजर नहीं आता. द्वारका नगर क्षेत्र में मानसून के मौसम में हर साल भारी जलभराव होता है. इसके परिणामस्वरूप, नागरिकों को परिवहन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और दैनिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. नागरिकों का यह भी कहना है कि जमा हुआ पानी मच्छरों के प्रजनन का केंद्र बन जाता है और संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा निर्माण करता है.

जल निकासी की व्यवस्था की मांग

नप प्रशासन को केवल कागजी कार्रवाई करने के बजाय, संबंधित स्थानों पर पक्की नालियां बनाकर जल निकासी की एक प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए. ज्ञापन में मांग की गई कि नाले का निर्माण तत्काल शुरू किया जाए और क्षेत्र के नागरिकों को समस्या से राहत प्रदान की जाए. द्वारका नगर के नागरिकों ने मांग की है कि नप प्रशासन मानसून के मौसम में जलभराव से निपटने के लिए नालियों के निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करें. प्रतिनिधि मंडल में हेमराज चौधरी, मुरलीधर करंडे, राजेश नंदेश्वर, ज्ञानीराम बनोटे, शुभम कथलेवार, दिनेश ढोक, माया कथलेवार, बबिता चौधरी, रंजिता करंडे, नम्रता भेलावे, सुखवंता बनोटे आदि का समावेश था.

मार्ग पर दरारें, भारी वाहनों से खतरा, दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी

खस्ताहाल सड़क बनी परेशानी

संवाददाता / तिरोड़ा

मनसर-तुमसर-तिरोड़ा-गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदारों की वजह से सीमेंट सड़क खस्ताहाल हो गई है. मार्ग पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है. इसके कारण कई नागरिकों को गड्ढे से होकर गुजरते समय दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवानी पड़ रही है. तुमसर से तिरोड़ा और तिरोड़ा से गोंदिया के बीच की सड़क में कुछ ही महीनों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं.

सड़क की कर दी मरहमपट्टी इन दरारों को छिपाने के लिए ठेकेदार द्वारा लगाई गई सीमेंट की 'मरहमपट्टी' महज दो महीने में ही उखड़ गई है. जिससे करोड़ों रु. का भ्रष्टाचार होने के आरोप लग रहे हैं. मनसर, देवाड़ी, मुंड़ीकोटा, तिरोड़ा की सड़कों पर 10 से 15 मीटर तक गहरी दरारें हैं. ठेकेदार ने इन दरारों को सीमेंट से ऐसे भर दिया मानो मरीज को टांके लगाए हो.

तिरोड़ा में एशिया का सबसे बड़ा अदानी पावर स्टेशन है, और परियोजना से कोयला और राख के परिवहन के लिए सैकड़ों टिप्पर दिन-रात चलते हैं. साथ ही कृषि उत्पादन बाजार समिति का शहर होने के कारण यहां भारी वाहनों का आवागमन लगा रहता है. ऐसे में नागरिकों ने गंभीर सवाल उठाया है कि ये कमजोर मार्ग भारी वाहनों का भार कैसे संभालेंगे. मनसर-तुमसर-तिरोड़ा-गोंदिया सड़क चौड़ीकरण कार्य को 2020-21 में मंजूरी दी गई थी. पांच-छह वर्ष बाद भी तुमसर से तिरोड़ा और तिरोड़ा से गोंदिया के बीच काम बहुत धीमी गति से चल रहा है. अब मंजूरी न मिलने का हवाला दे रहे.

संपादकीय

भारत में सूखे के आसार

भारत सरकार को उर्वरक, खाद सबसिडी ३.४२ लाख करोड़ रुपए करनी पड़ सकती है। यह सबसिडी कंपनियों को दी जाएगी, ताकि वे खाद का पर्याप्त बंदोबस्त कर सकें। बजट में इस सबसिडी का करीब १.७१ लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया था। खाद के संकट के साथ देश की खाद्य-सुरक्षा भी जुड़ी है। यदि कमजोर मॉनसून और अल नीनो के कारण, खाद के अभाव में, उपज कम हुई, तो खाद्यान्न की कमी के कारण देश में खाद्य-संकट के हालात भी बन सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ गेहूं, चावल, दलहन की उपज कम आंक रहे हैं, लिहाजा उनके आकलन हैं कि दक्षिण एशिया में सूखे के गंभीर आसार बन रहे हैं। उन देशों में भारत भी शामिल है। फिलहाल सरकार दावा कर रही है कि खाद्यान्न के भंडार भरे हैं, लेकिन बुनियादी समस्या उर्वरक और एलएनजी की है। हमें दोनों का आयात करना पड़ता है। करीब ५९ फीसदी एलएनजी खाड़ी देशों से आयात होती रही है, जिसमें करीब ४३ फीसदी एलएनजी अकेला कतर हमें सप्लाई करता था। ईरान युद्ध के दौरान मिसाइल हमलों से कतर की रिफाइनरी, एलएनजी के ढांचे, तेल के अन्य ठिकाने नष्ट हुए हैं, लिहाजा कतर को उत्पादन बहुत कम करना पड़ा है, नतीजतन आपूर्ति बाधित है। भारत में अब खरीफ की फसलों की बुवाई का समय है। धान, ईख, मक्का आदि मुख्य फसलें हैं। खाद का भारत का आयात बिल करीब ७४ लाख करोड़ रुपए है। सरकार के प्रतिनिधि किसानों को सलाह दे रहे हैं कि यूरिया, डीएपी खाद का इस्तेमाल कम करें। जैविक, प्राकृतिक खेती पर फोकस है, लेकिन सरकारी अधिकारी यह नहीं जानते कि प्राकृतिक खेती के लिए औसत खेत तीन साल में तैयार होता है। यह खेती छोटे भू-भाग पर भी नहीं की जा सकती। किसान जिस खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसका एक मोटा हिस्सा जमीन के भीतर रिस कर और भूमिगत जल के साथ मिल कर आसपास के खेतों में चला जाता है। उससे जैविक खेती प्रभावित, खादयुक्त हो जाती है। फिर वह प्राकृतिक खेती रहती ही नहीं। भारत में करीब ६.०१ करोड़ टन खाद की सालाना खपत होती है। बेशक ९० फीसदी एनपीके का उत्पादन देश में ही किया जाता है और ८७ फीसदी यूरिया का उत्पादन भी हम करने में सक्षम हैं, लेकिन उर्वरक संयंत्रों को चलाने के लिए भी एलएनजी चाहिए।

खाड़ी, पश्चिम एशिया में अब भी युद्ध जारी है। बेशक राष्ट्रपति ट्रंप समझौते और युद्धविराम के ढोंग करते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि वह युद्ध खत्म करना ही नहीं चाहते। अमरीका का एक तबका युद्ध से डॉलर छाप रहा है। बमबारी जारी है। ईरान ने भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन के अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले कर उन्हें तबाह किया है। युद्ध के कारण तेल, गैस, खाद और खासकर एलएनजी के आयात और आपूर्ति दोनों ही बाधित हैं। इनके कारण और कमजोर मॉनसून, अल नीनो के प्रभाव से भारत के राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और कर्नाटक आदि राज्यों में सूखे, खाद्य-संकट के आसार बन रहे हैं। कम उत्पादन के कारण चावल, दालों, सब्जियों की आपूर्ति और उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। उससे खाद्य मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी की आशंका है। विश्व में २६.६ करोड़ लोग सूखे और खाद्य-संकट के शिकार हो चुके हैं। उन देशों में एशिया के भी कई देश हैं, लेकिन शुक्र है कि भारत फिलहाल उस जमात में नहीं है। सरकारों ने सूखे से निबटने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाई हैं। फसल विविधीकरण के प्रयास भी जारी हैं, लेकिन किसान की उपज पर्याप्त नहीं होगी, तो वह बाजार में क्या बेचेगा? यदि व्यापार अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी? औसत किसान आज भी १०,००० रुपए माहवार कमा पाता है। उसमें भी खेती की आमदनी कम और मजदूरी का मेहनताना ज्यादा है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के १२ साल पूरे करने का जश्न भाजपा-एनडीए मनाए, लेकिन देश का औसत किसान कब जश्न मना पाएगा, यह भी यक्ष-प्रश्न से कम नहीं है। खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि किसानों की आमदनी में पर्याप्त इजाफा नहीं हो पा रहा है। गांवों के लोग अब खेती को छोड़ रहे हैं और मजदूर बनकर अपना गुजारा कर रहे हैं। खेती को लाभदायक बनाने की घोषणाएं होती हैं, पर हकीकत इससे दूर है।

नकली बीज और महंगे दाम में खाद बेची, तो कार्रवाई

जिले में 'मोबाइल' टीमों को और सक्रिय बनाने के लिए जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा के निर्देश

संवाददाता । गढ़चिरोली

खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और सही दाम में बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध हो, साथ ही नकली बीज की बिक्री, जमाखोरी और ज्यादा दाम में खाद बेचने जैसी चीजों पर रोक लगे, इसके लिए एमआरपी से अधिक दाम में स्वाद या बीज बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ-साथ ही उनका लाइसेंस रद्द कराने के निर्देश जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने दिए.

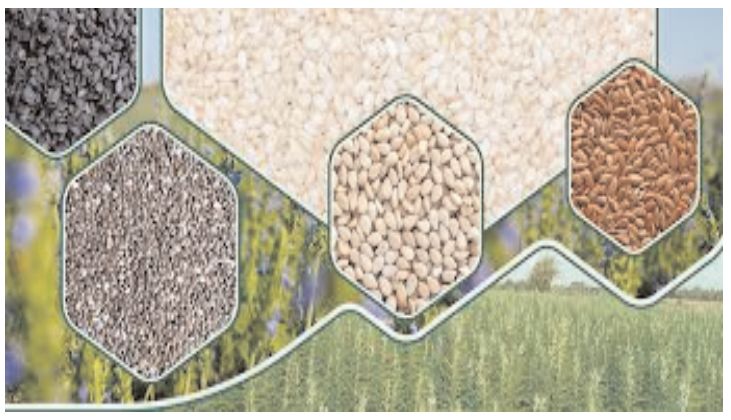

जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृर में मंगलवार, 16 जून को आयोजित 'कृषि निवेश उपलब्धता और गुणवत्ता नियंत्रण' विषय पर जिलास्तरीय समीक्षा बैठक में वे बोल रहे थे. बैठक में जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रीति हिरलकर, जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी किरण खोमणे सहित अभियान अधिकारी, जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, कृषि विभाग के अधिकारी, बीज और खाद कंपनियों के प्रतिनिधि तथा जिला डीलर्स और रिटेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे. खरीफ मौसम को बिना किसी मुश्किल के सफल बनाने के लिए राजस्व, कृषि और पुलिस प्रशासन को आपस में समन्वय करके काम करने के निर्देश दिए गए. किसानों की शिकायतों का तुरंत निवारण हो, इसके लिए जिला स्तर पर विशेष निष्ठा शिकायत निवारण कक्ष बनाया गया है. बीज, खाद या कीटनाशकों के बारे में कोई भी शिकायत हो, तो किसानों से सीधे कृषि विभाग से संपर्क करने की अपील की गई है. शिकायत निवारण कक्ष (8275690169 मोबाईल नंबर) उपलब्ध कराया गया है.

जरूरत के अनुसार खाद खरीदने की अपील

खरीफ सीजन की पृष्ठभूमि में जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने की जानकारी बैठक में दी गई. जिले में 1,494 मीट्रिक टन यूरिया और 200 मीट्रिक टन डीएपी खाद का बफर स्टॉक उपलब्ध है. मानसून में दूरदराज़ इलाकों में परिवहन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील हिस्सों में अतिरिक्त खाद का स्टॉक उपलब्ध कराया गया है. इसलिए किसानों से अपील की गई है कि अफवाहों पर भरोसा न करें और जरूरत के अनसार ही खाद खरीदें.

ट्रक-कार की टक्कर में २ की मौत

तीन गंभीर घायल, यवतमाल में दारव्हा मार्ग पर जामवाड़ी तालाब के पास

यवतमाल : दारव्हा मार्ग पर जामवाड़ी तालाब के समीप बुधवार को सुबह आठ बजे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक महिला और दो वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में रेणुका तुकाराम चव्हाण (55) और तृप्ति सूरज चव्हाण (2) का समावेश है. वहीं सूरज तुकाराम चव्हाण, मनीषा सूरज चव्हाण तथा चालक पवन नंदू चव्हाण घायल हैं. यह सभी अर्जुना गांव के निवासी हैं. चव्हाण परिवार कार (एमएच-29 सीजे-2048) से दारव्हा की ओर जा रहा था. इसी दौरान जामवाड़ी तालाब के पास सामने से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी.

यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे और पीछे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही लाइखेड़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से यवतमाल के सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रेणुका चव्हाण और दो वर्षीय तृप्ति चव्हाण को मृत घोषित कर दिया. अन्य तीन घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है. पुलिस के अनुसार दुर्घटना में शामिल ट्रक की पहचान नहीं हो सकी है. हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.

'स्मार्ट मीटर' के खिलाफ २५ को निकलेगा मोर्चा

नागरिक संघर्ष समिति की बैठक में किया गया निर्णय : पुलिस की मौजूदगी में डरा-धमकाकर मीटर बदलने का आरोप

संवाददाता । नागपुर

नागपुर में महावितरण द्वारा जबरन 'स्मार्ट और प्रीपेड' बिजली मीटर लगाए जाने के खिलाफ नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है. 'स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समिति' की एक अहम बैठक बुधवार को परवाना भवन में संपन्न हुई. बैठक में महावितरण द्वारा पुलिस की मौजूदगी में डरा-धमकाकर मीटर बदलने और उपभोक्ताओं को धमकी भरे मैसेज भेजने के तानाशाही रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की गई. इसके विरोध में समिति ने नागपुर शहर में एक तीव्र आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया है.

इस बैठक में मोहन शर्मा, डॉ. युगल रायलू, अरुण लाटकर, अशोक दगड़े, नरेश निमजे, बाबा शेलके, सी.एम. मौर्य, राहुल बंसोड़, रवींद्र पराते, विजय बाभुलकर, नरेश राऊत, शंकरराव काले आदि उपस्थित थे. समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में स्पष्ट घोषणा की थी कि घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे. इसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था. लेकिन अब महावितरण मुख्यमंत्री की घोषणा को ताक पर रखकर दोबारा जबरन मीटर थोप रहा है. इस तानाशाही के खिलाफ गुरुवार, 25 जून को वेराइटी चौक से एक विशाल मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री से महावितरण के जनविरोधी फैसले पर कार्रवाई की मांग की जाएगी. आंदोलन की अगली रणनीति तय करने के लिए सोमवार, 22 जून को शाम 5 बजे परवाना भवन में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की एक आम सभा बुलाई गई है.

समिति का मानना है कि स्मार्ट मीटर योजना बिजली क्षेत्र के निजीकरण की ओर एक बड़ा कदम है. महावितरण के ढाई करोड़ चालू मीटरों को हटाकर कबाड़ में फेंकने से जो आर्थिक नुकसान होगा, उसका बोझ अंततः बिजली बिल बढ़ाकर जनता से ही वसूला जाएगा. सरकार 'सुधार' के नाम पर आम जनता की संपत्ति को अडानी, अंबानी और टोरेंट जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपने का रास्ता साफ कर रही है.

नियमित जलापूर्ति करने के लिए निकाला गागर मोर्चा

मूलः शहर की जलापूर्ति की समस्या सुलझाने की मांग को लेकर मूल शहर भाजपा ने गागर मोर्चा निकाला. स्थानीय रामलीला भवन से निकाले गए इस मोर्चे में सैकड़ो महिलाएं शामिल हुईं. वह अपने सिर पर गागर/मटका लेकर निकल पड़ी थी. मोर्चा मूल नगर परिषद पहुंचने पर भाजपा की ओर से मुख्याधिकारी संदीप दोड़े को ज्ञापन दिया. महिलाओं ने नगर परिषद के सामने गागर फोड़कर विरोध जताया.

ज्ञापन में गत चार दिनों से नगर परिषद के नलों द्वारा जलापूर्ति न होने पर नागरिकों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है. बार-बार मांग करने के बावजूद यह समस्या सुलझी नहीं है. इस बात का जिक्र करते हुए तकनीकी समस्या को शीघ्र सुलझाया जाए, जरूरत पडने पर टैंकर द्वारा जलापूर्ति की जाए आदि विभिन्न मांगों का ज्ञापन दिया गया. मुख्याधिकारी दोड़े ने जलापूर्ति होने में आने वाली दिक्कतें बताई और उसे जल्द ही सुलझाने का आश्वासन दिया. भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण मोहुर्ले के नेतृत्व में निकाले गए इस मोर्चे में अजय गोगुलवार, नंदू रणदीवे, पार्षद अश्विनी निकोड़े, प्राची आक्केवार, किरण कापगते, राकेश ठाकरे, किशोर कापगते, मिलिंद खोबरागड़े, युवराज चावरे, उषा शेंडे, अविनाश जगताप कार्यकर्ता शामिल थे.

लंबित मांगों को पूरा करें : सांसद काले

वर्धा : राज्य की मध्याह्न भोजन (स्कूली पोषण आहार) योजना में कार्यरत हजारों कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर सांसद अमर काले ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया. काले ने मंत्री अदिती तटकरे को पत्र लिखकर कर्मियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है.

महाराष्ट्र स्कूली पोषक आहार कर्मचारी संघ फेडरेशन (सीआईटीयू) की ओर से सांसद अमर काले को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया. इन मांगों को जायज बताते हुए सांसद काले ने तुरंत ही महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे को पत्र भेजकर कर्मियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की. ज्ञापन में बताया कि 5 जुलाई 2024 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पोषक आहार

कर्मियों के मानधन में प्रतिमाह 1,000 रुपए की वृद्धि का निर्णय था. हालांकि, अब तक इस का लाभ कर्मियों को नहीं मिला है. ऐसे में बढ़े हुए मानधन को तत्काल लागू करने और बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गई कहा कि प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करने वाले कर्मियों को न्यूनतम 18 हजार रुपए मासिक मानधन दिया जाए. इसके अलावा वर्तमान में केवल 10 माह के लिए मिलने वाले मानधन को पूरे 12 माह तक जारी रखने, छात्र संख्या कम होने के कारण सेवा से हटाए गए कर्मियों को पुनः नियुक्त करने तथा पेंशन, पीएफ, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई.

सेलू में उखड़ी सड़कें, व्यापारियों को नुकसान और प्रशासन की उदासीनता

करोड़ों की योजना बनी सिरदर्द : एक बार सड़क खोदने के बाद दोबारा मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दे रहा ठेकेदार

संवाददाता । सेलू

शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा ४४ करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी जल योजना को मंजूरी दी थी. लेकिन योजना का लाभ अब तक नागरिकों तक नहीं पहुंच सका है. इसके विपरीत, शहर के लोग उखड़ी हुई सड़कों, धूल-धक्कड़ और भारी असुविधाओं को झेलने को मजबूर हैं.

ऐसे में नागरिकों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि यह जल योजना आखिर जनता के लिए है या ठेकेदारों के हितों के लिए?

शहर के प्रमुख और अत्यधिक व्यस्त मार्ग संत केजाजी मार्ग से मटन मार्केट तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क की खुदाई की गई. लेकिन खुदाई के दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सड़क को पूर्ववत नहीं किया है. परिणामस्वरुप नागरिकों, और वाहन चालकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. यह मार्ग शहर की मुख्य बाजारपेठ की जीवनरेखा माना जाता है. सड़क उखड़े रहने के कारण ग्राहकों की आवाजाही में भारी कमी आई है, जिससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है. कई दुकानदारों ने बताया कि उनके दैनिक व्यापार में बड़ी गिरावट आई है और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. नागरिकों का आरोप है कि संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी काम को समय पर पूरा करने के बजाय अन्य हितों में अधिक रुचि दिखा रहे हैं. सड़क खोदने में जिस तेजी का प्रदर्शन किया गया, उसी तत्परता से कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है. नागरिकों का कहना है कि वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर आदेश देने वाले अधिकारी जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान बने हुए हैं. इधर ठेकेदार की लापरवाही और कार्य में हो रही देरी के कारण लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. मानसून की शुरुआत के साथ स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है.

खुले पड़े गड्ढे, कीचड़ और यातायात बाधाओं के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. चिंताजनक बात यह है कि नगर पंचायत प्रशासन, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और नगरसेवक जैसे जिम्मेदार लोग इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस भूमिका निभाते नजर नहीं आ रहे हैं. नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई या जवाबदेही तय करने को लेकर कोई खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है। आज सेलू के नागरिकों के मन में कई सवाल हैं- ४४ करोड़ रुपये की जल योजना का वास्तविक लाभ उन्हें कब मिलेगा? उखड़ी हुई सड़कें कब दुरुस्त होंगी? व्यापारियों

को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब देना अब प्रशासन, नगर पंचायत और संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी है. अन्यथा नागरिकों का बढ़ता आक्रोश आने वाले समय में बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकता है.

वैनगंगा नदी पर बैराजों का जाल, १९८ गांवों को लाभ

संवाददाता । गढ़चिरोली

पूर्व विदर्भ में जलसंकट दूर कर किसानों को समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वैनगंगा नदी पर बैराजों का जाल बिछाने की महत्वाकांक्षी पहल शुरु की है. गढ़चिरोली और चंद्रपुर जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए नदी पर पूर्ण, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित बैराजों के माध्यम से दोनों जिलों के १९८ गांवों की ५३,६२२ हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा.

इस योजना के पीछे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदर्शी सोच महत्वपूर्ण रही है. वर्ष २०२४ से वैनगंगा नदी के जलसंसाधनों का प्रभावी उपयोग कर पूर्व विदर्भ को जलसमृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं. नदी पर चरणबद्ध तरीके से बैराजों के निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, किसानों को एक से अधिक फसलें लेने का अवसर मिलेगा तथा सतत जल प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसी दृष्टिकोण के साथ योजना का क्रियान्वयन अब धरातल पर आकार लेता दिखाई दे रहा है.

पूर्व विदर्भ में हजारों हेक्टेयर में होगी सिंचाई

उपसा सिंचाई योजनाओं को लाभः चंद्रपुर की गोंडपिपरी तहसील में प्रस्तावित ऐनबोथला बैराज से बोरगांव, नांदगांव, भननारहेटी और रामपुर-चंदनखेड़ी उपसा सिंचाई योजनाओं को पानी उपलब्ध कराने की योजना है. इस परियोजना के माध्यम से ६९ गांवों की कुल २४,२६१ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलने की उम्मीद है. परियोजना जिले की औद्योगिक जल आवश्यकता को भी अंशतः पूरा करेगी.

चंद्रपुर मनपा में आईएएस अधिकारी ने तोड़ा प्रोटोकॉल

चंद्रपुर : चंद्रपुर मनपा में इन दिनों सत्ताधारी तथा विपक्षी पार्टी में जारी संघर्ष सर्वविदित है. इस बीच आज चौंकाने वाली खबर आई है. चंद्रपुर मनपा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि आयुक्त के रुप में पदस्थ आईएएस अधिकारी प्रोटोकॉल को तोड़ महापौर तथा सत्ताधारी पार्टी के साथ प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनकर मनपा के लिए निधि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे. आज चंद्रपुर मनपा की महापौर संगीता खांडेकर तथा स्थायी समिति सभापति मनस्वी गिरहे के साथ प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर आईएएस अधिकारी अकुनूरी नरेश जिलाधिकारी वसुमना पंत से मिले. साथ ही जिलाधिकारी वसुमना पंत को दिए जा रहे ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रुप में फोटो भी खिंचवाई. इससे आईएएस अधिकारी अकुनूरी नरेश की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे है.

चंद्रपुर शहर के समग्र विकास में तेजी लाने और नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, चंद्रपुर मनपा की महापौर संगीता खांडेकर ने चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना से मुलाकात की. मनपा आयुक्त अकुनूरी नरेश, स्थायी समिति की सभापति मनस्वी गिरे, उप महापौर प्रशांत दानव, सदन की नेता जयश्री जुमडे और पार्षद सुनीता जायसवाल की उपस्थिति में विभिन्न विकास योजनाओं के तहत स्वीकृत राशि में वृद्धि के संबंध में ज्ञापन दिया.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में चंद्रपुर मनपा को महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती शहरी उत्थान महाअभियान (जिला स्तर) के तहत 5.89 करोड़, लोकशाहिर अन्नभाऊ साठे शहरी दलित बस्ती सुधार योजना के तहत 7.50 करोड़ और शहरी बस्ती सुधार योजना के तहत 15.00 लाख की निधि स्वीकृत की गई है.

पिछले पांच वर्षों में निधि वितरण के औसत, शहर की बढ़ती जनसंख्या, नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त निधि अपर्याप्त है. महापौर खांडेकर ने कहा कि इस बढ़ी हुई धनराशि से शहर की सड़कों, नालियों, जल आपूर्ति, स्वच्छता, दलित बस्ती विकास, बुनियादी नागरिक सुविधाओं और विभिन्न विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

कलमेश्वर-ब्राह्मणी न.प. में आग का तांडव, नगराध्यक्ष का केबिन खाक

कम्प्यूटर और जरुरी दस्तावेज जलकर नष्ट, लाखों का नुकसान

कलमेश्वर : कलमेश्वर-ब्राह्मणी नगरपरिषद के प्रशासनिक कार्यालय में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से नगराध्यक्ष का कक्ष, कई कम्प्यूटर, फर्नीचर व महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. सुबह करीब 5 बजे कर्मचारी गुंडेराव कुमरे को कार्यालय से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं. उन्होंने कलमेश्वर नगरपरिषद के दमकल दल को सूचना दी. दमकल टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरु किया. आग की तीव्रता अधिक होने से वाडी, सावनेर व मोहपा नगर परिषदों से दमकल सहायता बुलानी पड़ी. करीब 2 घंटे में आग बुझाई गई.

सूचना मिलते ही थानेदार मनोज कालवाडे पुलिस बल के साथ पहुंचे. वहीं, विधायक आशीष देशमुख, भाजपा नेता डॉ. राजीव पोतदार, मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर, नगराध्यक्ष अविनाश माकोड़े, उपाध्यक्ष धनराज देवके, महावितरण के इंजीनियर और नगरसेवक भी मौके पर पहुंचे. इस बीच, सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने नगरपरिषद कार्यालय का दौरा कर आग की घटना की समीक्षा की. मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर ने निरीक्षण कर सुरक्षित दस्तावेजों की पुष्टि की. नगरपरिषद का कामकाज सुचारू रखने के लिए 18 जून से नगर भवन परिसर में नियमित कार्य शुरु करने की जानकारी दी गई. भाजपा नेता डॉ. राजीव पोतदार ने आग लगने के कारणों की गहन जांच की मांग की है.

लाखों के नुकसान की आशंका

आग में नगराध्यक्ष का पूरा कैबिन जलकर खाक हो गया, साथ ही उससे सटे स्थापना विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आवक-जावक विभाग के दस्तावेज, कम्प्यूटर और फर्नीचर पूरी तरह नष्ट हो गए. कार्यालय में रखी लोहे की अलमारियां, पंखे, कम्प्यूटर और अन्य सामग्री भी जलकर राख हो गई, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, निर्माण विभाग, संपत्ति कर (घर टैक्स) विभाग, लेखा विभाग, जन्म-मृत्यु पंजीकरण विभाग और जलापूर्ति विभाग आग की चपेट में नहीं आए, इसलिए इन विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

दो वाहन खाक, दो वाहन भी आधे जले

नागपुरः आराधना नगर के एक गैराज में खड़े चार वाहनों में रहस्यमय तरीके से आग लगने से 2 वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि 1 वाहन आधा और स्क्रैप हो चुका दूसरा वाहन भी आधा जल गया. दमकल अधिकारी के अनुसार आग का कारण पता नहीं चला. जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. दमकल विभाग को सुबह करीब 6.09 बजे आराधना नगर बस स्टॉप के पास के साहिल गैराज में आग लगने की सूचना मिली. ऐसे में वाठोड़ा दमकल केंद्र से 1 फायर टेंडर, 1 बाउजर व 1 छोटा फायर टेंडर भेजा गया. दमकलकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाकर आग पर काबू पाया. उसके बाद कूलिंग प्रक्रिया शुरु की गई. आग पर समय रहते काबू नहीं किया जाता तो आसपास की इमारतों को भी चपेट में ले लेता. दमकल विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार गैराज अनंत सुधाकर काले का है. आग में एमएच 47 वाई 9867 और एमएच 41 वाई 3646 जलकर खाक हो गई. जबकि गाड़ी क्रमांक एमएच 31 एफसी 5005 आधी और एमएच 31 सीक्यू 9047 क्रमांक की स्क्रैप हो चुकी गाड़ी आधी जली. दमकल विभाग ने 15 लाख रु. का नुकसान होने की बात कही है. वाठोड़ा दमकल केंद्र के अधिकारी चंद्रशेखर रणदिवे के नेतृत्व में आग पर काबू पाया गया. उधर, रघुजीनगर में संजय पाटिल की केक गैलरी नामक शॉप में बुधवार दोपहर 3.50 बजे आग लग गई. इससे 10 लाख रु का नुकसान होने का अंदेशा दमकल विभाग ने जताया है.

संपादकीय

भारत में सूखे के आसार

भारत सरकार को उर्वरक, खाद सबसिडी ३.४२ लाख करोड़ रुपए करनी पड़ सकती है। यह सबसिडी कंपनियों को दी जाएगी, ताकि वे खाद का पर्याप्त बंदोबस्त कर सकें। बजट में इस सबसिडी का करीब १.७१ लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया था। खाद के संकट के साथ देश की खाद्य-सुरक्षा भी जुड़ी है। यदि कमजोर मॉनसून और अल नीनो के कारण, खाद के अभाव में, उपज कम हुई, तो खाद्यान्न की कमी के कारण देश में खाद्य-संकट के हालात भी बन सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ गेहूं, चावल, दलहन की उपज कम आंक रहे हैं, लिहाजा उनके आकलन हैं कि दक्षिण एशिया में सूखे के गंभीर आसार बन रहे हैं। उन देशों में भारत भी शामिल है। फिलहाल सरकार दावा कर रही है कि खाद्यान्न के भंडार भरे हैं, लेकिन बुनियादी समस्या उर्वरक और एलएनजी की है। हमें दोनों का आयात करना पड़ता है। करीब ५९ फीसदी एलएनजी खाड़ी देशों से आयात होती रही है, जिसमें करीब ४३ फीसदी एलएनजी अकेला कतर हमें सप्लाई करता था। ईरान युद्ध के दौरान मिसाइल हमलों से कतर की रिफाइनरी, एलएनजी के ढांचे, तेल के अन्य ठिकाने नष्ट हुए हैं, लिहाजा कतर को उत्पादन बहुत कम करना पड़ा है, नतीजतन आपूर्ति बाधित है। भारत में अब खरीफ की फसलों की बुवाई का समय है। धान, ईख, मक्का आदि मुख्य फसलें हैं। खाद का भारत का आयात बिल करीब ७४ लाख करोड़ रुपए है। सरकार के प्रतिनिधि किसानों को सलाह दे रहे हैं कि यूरिया, डीएपी खाद का इस्तेमाल कम करें। जैविक, प्राकृतिक खेती पर फोकस है, लेकिन सरकारी अधिकारी यह नहीं जानते कि प्राकृतिक खेती के लिए औसत खेत तीन साल में तैयार होता है। यह खेती छोटे भू-भाग पर भी नहीं की जा सकती। किसान जिस खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसका एक मोटा हिस्सा जमीन के भीतर रिस कर और भूमिगत जल के साथ मिल कर आसपास के खेतों में चला जाता है। उससे जैविक खेती प्रभावित, खादयुक्त हो जाती है। फिर वह प्राकृतिक खेती रहती ही नहीं। भारत में करीब ६.०१ करोड़ टन खाद की सालाना खपत होती है। बेशक ९० फीसदी एनपीके का उत्पादन देश में ही किया जाता है और ८७ फीसदी यूरिया का उत्पादन भी हम करने में सक्षम हैं, लेकिन उर्वरक संयंत्रों को चलाने के लिए भी एलएनजी चाहिए।

खाड़ी, पश्चिम एशिया में अब भी युद्ध जारी है। बेशक राष्ट्रपति ट्रंप समझौते और युद्धविराम के ढोंग करते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि वह युद्ध खत्म करना ही नहीं चाहते। अमरीका का एक तबका युद्ध से डॉलर छाप रहा है। बमबारी जारी है। ईरान ने भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन के अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले कर उन्हें तबाह किया है। युद्ध के कारण तेल, गैस, खाद और खासकर एलएनजी के आयात और आपूर्ति दोनों ही बाधित हैं। इनके कारण और कमजोर मॉनसून, अल नीनो के प्रभाव से भारत के राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और कर्नाटक आदि राज्यों में सूखे, खाद्य-संकट के आसार बन रहे हैं। कम उत्पादन के कारण चावल, दालों, सब्जियों की आपूर्ति और उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। उससे खाद्य मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी की आशंका है। विश्व में २६.६ करोड़ लोग सूखे और खाद्य-संकट के शिकार हो चुके हैं। उन देशों में एशिया के भी कई देश हैं, लेकिन शुक्र है कि भारत फिलहाल उस जमात में नहीं है। सरकारों ने सूखे से निबटने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाई हैं। फसल विविधीकरण के प्रयास भी जारी हैं, लेकिन किसान की उपज पर्याप्त नहीं होगी, तो वह बाजार में क्या बेचेगा? यदि व्यापार अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी? औसत किसान आज भी १०,००० रुपए माहवार कमा पाता है। उसमें भी खेती की आमदनी कम और मजदूरी का मेहनताना ज्यादा है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के १२ साल पूरे करने का जश्न भाजपा-एनडीए मनाए, लेकिन देश का औसत किसान कब जश्न मना पाएगा, यह भी यक्ष-प्रश्न से कम नहीं है। खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि किसानों की आमदनी में पर्याप्त इजाफा नहीं हो पा रहा है। गांवों के लोग अब खेती को छोड़ रहे हैं और मजदूर बनकर अपना गुजारा कर रहे हैं। खेती को लाभदायक बनाने की घोषणाएं होती हैं, पर हकीकत इससे दूर है।

नकली बीज और महंगे दाम में खाद बेची, तो कार्रवाई

जिले में 'मोबाइल' टीमों को और सक्रिय बनाने के लिए जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा के निर्देश

संवाददाता । गढ़चिरोली

खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और सही दाम में बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध हो, साथ ही नकली बीज की बिक्री, जमाखोरी और ज्यादा दाम में खाद बेचने जैसी चीजों पर रोक लगे, इसके लिए एमआरपी से अधिक दाम में स्वाद या बीज बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ-साथ ही उनका लाइसेंस रद्द कराने के निर्देश जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने दिए.

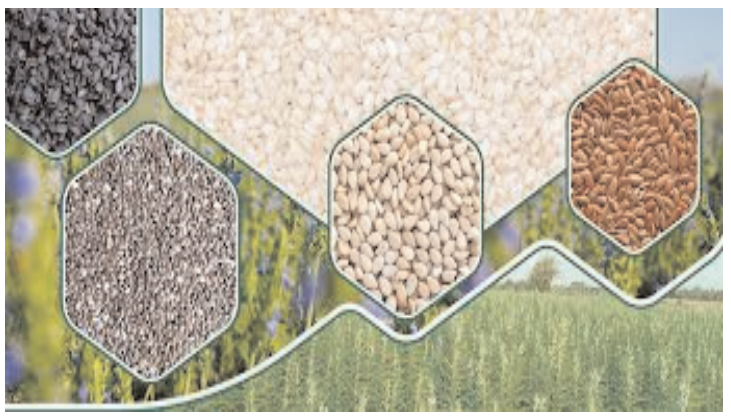

जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृर में मंगलवार, 16 जून को आयोजित 'कृषि निवेश उपलब्धता और गुणवत्ता नियंत्रण' विषय पर जिलास्तरीय समीक्षा बैठक में वे बोल रहे थे. बैठक में जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रीति हिरलकर, जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी किरण खोमणे सहित अभियान अधिकारी, जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, कृषि विभाग के अधिकारी, बीज और खाद कंपनियों के प्रतिनिधि तथा जिला डीलर्स और रिटेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे. खरीफ मौसम को बिना किसी मुश्किल के सफल बनाने के लिए राजस्व, कृषि और पुलिस प्रशासन को आपस में समन्वय करके काम करने के निर्देश दिए गए. किसानों की शिकायतों का तुरंत निवारण हो, इसके लिए जिला स्तर पर विशेष निष्ठा शिकायत निवारण कक्ष बनाया गया है. बीज, खाद या कीटनाशकों के बारे में कोई भी शिकायत हो, तो किसानों से सीधे कृषि विभाग से संपर्क करने की अपील की गई है. शिकायत निवारण कक्ष (8275690169 मोबाईल नंबर) उपलब्ध कराया गया है.

जरूरत के अनुसार खाद खरीदने की अपील

खरीफ सीजन की पृष्ठभूमि में जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने की जानकारी बैठक में दी गई. जिले में 1,494 मीट्रिक टन यूरिया और 200 मीट्रिक टन डीएपी खाद का बफर स्टॉक उपलब्ध है. मानसून में दूरदराज़ इलाकों में परिवहन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील हिस्सों में अतिरिक्त खाद का स्टॉक उपलब्ध कराया गया है. इसलिए किसानों से अपील की गई है कि अफवाहों पर भरोसा न करें और जरूरत के अनसार ही खाद खरीदें.

ट्रक-कार की टक्कर में २ की मौत

तीन गंभीर घायल, यवतमाल में दारव्हा मार्ग पर जामवाड़ी तालाब के पास

यवतमाल : दारव्हा मार्ग पर जामवाड़ी तालाब के समीप बुधवार को सुबह आठ बजे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक महिला और दो वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में रेणुका तुकाराम चव्हाण (55) और तृप्ति सूरज चव्हाण (2) का समावेश है. वहीं सूरज तुकाराम चव्हाण, मनीषा सूरज चव्हाण तथा चालक पवन नंदू चव्हाण घायल हैं. यह सभी अर्जुना गांव के निवासी हैं. चव्हाण परिवार कार (एमएच-29 सीजे-2048) से दारव्हा की ओर जा रहा था. इसी दौरान जामवाड़ी तालाब के पास सामने से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी.

यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे और पीछे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही लाइखेड़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से यवतमाल के सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रेणुका चव्हाण और दो वर्षीय तृप्ति चव्हाण को मृत घोषित कर दिया. अन्य तीन घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है. पुलिस के अनुसार दुर्घटना में शामिल ट्रक की पहचान नहीं हो सकी है. हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.

'स्मार्ट मीटर' के खिलाफ २५ को निकलेगा मोर्चा

नागरिक संघर्ष समिति की बैठक में किया गया निर्णय : पुलिस की मौजूदगी में डरा-धमकाकर मीटर बदलने का आरोप

संवाददाता । नागपुर

नागपुर में महावितरण द्वारा जबरन 'स्मार्ट और प्रीपेड' बिजली मीटर लगाए जाने के खिलाफ नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है. 'स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समिति' की एक अहम बैठक बुधवार को परवाना भवन में संपन्न हुई. बैठक में महावितरण द्वारा पुलिस की मौजूदगी में डरा-धमकाकर मीटर बदलने और उपभोक्ताओं को धमकी भरे मैसेज भेजने के तानाशाही रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की गई. इसके विरोध में समिति ने नागपुर शहर में एक तीव्र आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया है.

इस बैठक में मोहन शर्मा, डॉ. युगल रायलू, अरुण लाटकर, अशोक दगड़े, नरेश निमजे, बाबा शेलके, सी.एम. मौर्य, राहुल बंसोड़, रवींद्र पराते, विजय बाभुलकर, नरेश राऊत, शंकरराव काले आदि उपस्थित थे. समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में स्पष्ट घोषणा की थी कि घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे. इसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था. लेकिन अब महावितरण मुख्यमंत्री की घोषणा को ताक पर रखकर दोबारा जबरन मीटर थोप रहा है. इस तानाशाही के खिलाफ गुरुवार, 25 जून को वेराइटी चौक से एक विशाल मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री से महावितरण के जनविरोधी फैसले पर कार्रवाई की मांग की जाएगी. आंदोलन की अगली रणनीति तय करने के लिए सोमवार, 22 जून को शाम 5 बजे परवाना भवन में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की एक आम सभा बुलाई गई है.

समिति का मानना है कि स्मार्ट मीटर योजना बिजली क्षेत्र के निजीकरण की ओर एक बड़ा कदम है. महावितरण के ढाई करोड़ चालू मीटरों को हटाकर कबाड़ में फेंकने से जो आर्थिक नुकसान होगा, उसका बोझ अंततः बिजली बिल बढ़ाकर जनता से ही वसूला जाएगा. सरकार 'सुधार' के नाम पर आम जनता की संपत्ति को अडानी, अंबानी और टोरेंट जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपने का रास्ता साफ कर रही है.

नियमित जलापूर्ति करने के लिए निकाला गागर मोर्चा

मूलः शहर की जलापूर्ति की समस्या सुलझाने की मांग को लेकर मूल शहर भाजपा ने गागर मोर्चा निकाला. स्थानीय रामलीला भवन से निकाले गए इस मोर्चे में सैकड़ो महिलाएं शामिल हुईं. वह अपने सिर पर गागर/मटका लेकर निकल पड़ी थी. मोर्चा मूल नगर परिषद पहुंचने पर भाजपा की ओर से मुख्याधिकारी संदीप दोड़े को ज्ञापन दिया. महिलाओं ने नगर परिषद के सामने गागर फोड़कर विरोध जताया.

ज्ञापन में गत चार दिनों से नगर परिषद के नलों द्वारा जलापूर्ति न होने पर नागरिकों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है. बार-बार मांग करने के बावजूद यह समस्या सुलझी नहीं है. इस बात का जिक्र करते हुए तकनीकी समस्या को शीघ्र सुलझाया जाए, जरूरत पडने पर टैंकर द्वारा जलापूर्ति की जाए आदि विभिन्न मांगों का ज्ञापन दिया गया. मुख्याधिकारी दोड़े ने जलापूर्ति होने में आने वाली दिक्कतें बताई और उसे जल्द ही सुलझाने का आश्वासन दिया. भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण मोहुर्ले के नेतृत्व में निकाले गए इस मोर्चे में अजय गोगुलवार, नंदू रणदीवे, पार्षद अश्विनी निकोड़े, प्राची आक्केवार, किरण कापगते, राकेश ठाकरे, किशोर कापगते, मिलिंद खोबरागड़े, युवराज चावरे, उषा शेंडे, अविनाश जगताप कार्यकर्ता शामिल थे.

लंबित मांगों को पूरा करें : सांसद काले

वर्धा : राज्य की मध्याह्न भोजन (स्कूली पोषण आहार) योजना में कार्यरत हजारों कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर सांसद अमर काले ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया. काले ने मंत्री अदिती तटकरे को पत्र लिखकर कर्मियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है.

महाराष्ट्र स्कूली पोषक आहार कर्मचारी संघ फेडरेशन (सीआईटीयू) की ओर से सांसद अमर काले को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया. इन मांगों को जायज बताते हुए सांसद काले ने तुरंत ही महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे को पत्र भेजकर कर्मियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की. ज्ञापन में बताया कि 5 जुलाई 2024 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पोषक आहार

कर्मियों के मानधन में प्रतिमाह 1,000 रुपए की वृद्धि का निर्णय था. हालांकि, अब तक इस का लाभ कर्मियों को नहीं मिला है. ऐसे में बढ़े हुए मानधन को तत्काल लागू करने और बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गई कहा कि प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करने वाले कर्मियों को न्यूनतम 18 हजार रुपए मासिक मानधन दिया जाए. इसके अलावा वर्तमान में केवल 10 माह के लिए मिलने वाले मानधन को पूरे 12 माह तक जारी रखने, छात्र संख्या कम होने के कारण सेवा से हटाए गए कर्मियों को पुनः नियुक्त करने तथा पेंशन, पीएफ, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई.

सेलू में उखड़ी सड़कें, व्यापारियों को नुकसान और प्रशासन की उदासीनता

करोड़ों की योजना बनी सिरदर्द : एक बार सड़क खोदने के बाद दोबारा मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दे रहा ठेकेदार

संवाददाता । सेलू

शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा ४४ करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी जल योजना को मंजूरी दी थी. लेकिन योजना का लाभ अब तक नागरिकों तक नहीं पहुंच सका है. इसके विपरीत, शहर के लोग उखड़ी हुई सड़कों, धूल-धक्कड़ और भारी असुविधाओं को झेलने को मजबूर हैं.

ऐसे में नागरिकों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि यह जल योजना आखिर जनता के लिए है या ठेकेदारों के हितों के लिए?

शहर के प्रमुख और अत्यधिक व्यस्त मार्ग संत केजाजी मार्ग से मटन मार्केट तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क की खुदाई की गई. लेकिन खुदाई के दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सड़क को पूर्ववत नहीं किया है. परिणामस्वरुप नागरिकों, और वाहन चालकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. यह मार्ग शहर की मुख्य बाजारपेठ की जीवनरेखा माना जाता है. सड़क उखड़े रहने के कारण ग्राहकों की आवाजाही में भारी कमी आई है, जिससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हुआ है. कई दुकानदारों ने बताया कि उनके दैनिक व्यापार में बड़ी गिरावट आई है और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. नागरिकों का आरोप है कि संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी काम को समय पर पूरा करने के बजाय अन्य हितों में अधिक रुचि दिखा रहे हैं. सड़क खोदने में जिस तेजी का प्रदर्शन किया गया, उसी तत्परता से कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है. नागरिकों का कहना है कि वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर आदेश देने वाले अधिकारी जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान बने हुए हैं. इधर ठेकेदार की लापरवाही और कार्य में हो रही देरी के कारण लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. मानसून की शुरुआत के साथ स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है.

खुले पड़े गड्ढे, कीचड़ और यातायात बाधाओं के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. चिंताजनक बात यह है कि नगर पंचायत प्रशासन, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और नगरसेवक जैसे जिम्मेदार लोग इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस भूमिका निभाते नजर नहीं आ रहे हैं. नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई या जवाबदेही तय करने को लेकर कोई खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है। आज सेलू के नागरिकों के मन में कई सवाल हैं- ४४ करोड़ रुपये की जल योजना का वास्तविक लाभ उन्हें कब मिलेगा? उखड़ी हुई सड़कें कब दुरुस्त होंगी? व्यापारियों

को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब देना अब प्रशासन, नगर पंचायत और संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी है. अन्यथा नागरिकों का बढ़ता आक्रोश आने वाले समय में बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकता है.

वैनगंगा नदी पर बैराजों का जाल, १९८ गांवों को लाभ

संवाददाता । गढ़चिरोली

पूर्व विदर्भ में जलसंकट दूर कर किसानों को समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वैनगंगा नदी पर बैराजों का जाल बिछाने की महत्वाकांक्षी पहल शुरु की है. गढ़चिरोली और चंद्रपुर जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए नदी पर पूर्ण, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित बैराजों के माध्यम से दोनों जिलों के १९८ गांवों की ५३,६२२ हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा.

इस योजना के पीछे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदर्शी सोच महत्वपूर्ण रही है. वर्ष २०२४ से वैनगंगा नदी के जलसंसाधनों का प्रभावी उपयोग कर पूर्व विदर्भ को जलसमृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं. नदी पर चरणबद्ध तरीके से बैराजों के निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, किसानों को एक से अधिक फसलें लेने का अवसर मिलेगा तथा सतत जल प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसी दृष्टिकोण के साथ योजना का क्रियान्वयन अब धरातल पर आकार लेता दिखाई दे रहा है.

पूर्व विदर्भ में हजारों हेक्टेयर में होगी सिंचाई

उपसा सिंचाई योजनाओं को लाभः चंद्रपुर की गोंडपिपरी तहसील में प्रस्तावित ऐनबोथला बैराज से बोरगांव, नांदगांव, भननारहेटी और रामपुर-चंदनखेड़ी उपसा सिंचाई योजनाओं को पानी उपलब्ध कराने की योजना है. इस परियोजना के माध्यम से ६९ गांवों की कुल २४,२६१ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलने की उम्मीद है. परियोजना जिले की औद्योगिक जल आवश्यकता को भी अंशतः पूरा करेगी.

चंद्रपुर मनपा में आईएएस अधिकारी ने तोड़ा प्रोटोकॉल

चंद्रपुर : चंद्रपुर मनपा में इन दिनों सत्ताधारी तथा विपक्षी पार्टी में जारी संघर्ष सर्वविदित है. इस बीच आज चौंकाने वाली खबर आई है. चंद्रपुर मनपा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि आयुक्त के रुप में पदस्थ आईएएस अधिकारी प्रोटोकॉल को तोड़ महापौर तथा सत्ताधारी पार्टी के साथ प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनकर मनपा के लिए निधि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे. आज चंद्रपुर मनपा की महापौर संगीता खांडेकर तथा स्थायी समिति सभापति मनस्वी गिरहे के साथ प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर आईएएस अधिकारी अकुनूरी नरेश जिलाधिकारी वसुमना पंत से मिले. साथ ही जिलाधिकारी वसुमना पंत को दिए जा रहे ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रुप में फोटो भी खिंचवाई. इससे आईएएस अधिकारी अकुनूरी नरेश की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे है.

चंद्रपुर शहर के समग्र विकास में तेजी लाने और नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, चंद्रपुर मनपा की महापौर संगीता खांडेकर ने चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना से मुलाकात की. मनपा आयुक्त अकुनूरी नरेश, स्थायी समिति की सभापति मनस्वी गिरे, उप महापौर प्रशांत दानव, सदन की नेता जयश्री जुमडे और पार्षद सुनीता जायसवाल की उपस्थिति में विभिन्न विकास योजनाओं के तहत स्वीकृत राशि में वृद्धि के संबंध में ज्ञापन दिया.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में चंद्रपुर मनपा को महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती शहरी उत्थान महाअभियान (जिला स्तर) के तहत 5.89 करोड़, लोकशाहिर अन्नभाऊ साठे शहरी दलित बस्ती सुधार योजना के तहत 7.50 करोड़ और शहरी बस्ती सुधार योजना के तहत 15.00 लाख की निधि स्वीकृत की गई है.

पिछले पांच वर्षों में निधि वितरण के औसत, शहर की बढ़ती जनसंख्या, नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त निधि अपर्याप्त है. महापौर खांडेकर ने कहा कि इस बढ़ी हुई धनराशि से शहर की सड़कों, नालियों, जल आपूर्ति, स्वच्छता, दलित बस्ती विकास, बुनियादी नागरिक सुविधाओं और विभिन्न विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

कलमेश्वर-ब्राह्मणी न.प. में आग का तांडव, नगराध्यक्ष का केबिन खाक

कम्प्यूटर और जरुरी दस्तावेज जलकर नष्ट, लाखों का नुकसान

कलमेश्वर : कलमेश्वर-ब्राह्मणी नगरपरिषद के प्रशासनिक कार्यालय में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से नगराध्यक्ष का कक्ष, कई कम्प्यूटर, फर्नीचर व महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. सुबह करीब 5 बजे कर्मचारी गुंडेराव कुमरे को कार्यालय से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं. उन्होंने कलमेश्वर नगरपरिषद के दमकल दल को सूचना दी. दमकल टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरु किया. आग की तीव्रता अधिक होने से वाडी, सावनेर व मोहपा नगर परिषदों से दमकल सहायता बुलानी पड़ी. करीब 2 घंटे में आग बुझाई गई.

सूचना मिलते ही थानेदार मनोज कालवाडे पुलिस बल के साथ पहुंचे. वहीं, विधायक आशीष देशमुख, भाजपा नेता डॉ. राजीव पोतदार, मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर, नगराध्यक्ष अविनाश माकोड़े, उपाध्यक्ष धनराज देवके, महावितरण के इंजीनियर और नगरसेवक भी मौके पर पहुंचे. इस बीच, सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने नगरपरिषद कार्यालय का दौरा कर आग की घटना की समीक्षा की. मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर ने निरीक्षण कर सुरक्षित दस्तावेजों की पुष्टि की. नगरपरिषद का कामकाज सुचारू रखने के लिए 18 जून से नगर भवन परिसर में नियमित कार्य शुरु करने की जानकारी दी गई. भाजपा नेता डॉ. राजीव पोतदार ने आग लगने के कारणों की गहन जांच की मांग की है.

लाखों के नुकसान की आशंका

आग में नगराध्यक्ष का पूरा कैबिन जलकर खाक हो गया, साथ ही उससे सटे स्थापना विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आवक-जावक विभाग के दस्तावेज, कम्प्यूटर और फर्नीचर पूरी तरह नष्ट हो गए. कार्यालय में रखी लोहे की अलमारियां, पंखे, कम्प्यूटर और अन्य सामग्री भी जलकर राख हो गई, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, निर्माण विभाग, संपत्ति कर (घर टैक्स) विभाग, लेखा विभाग, जन्म-मृत्यु पंजीकरण विभाग और जलापूर्ति विभाग आग की चपेट में नहीं आए, इसलिए इन विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

दो वाहन खाक, दो वाहन भी आधे जले

नागपुरः आराधना नगर के एक गैराज में खड़े चार वाहनों में रहस्यमय तरीके से आग लगने से 2 वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि 1 वाहन आधा और स्क्रैप हो चुका दूसरा वाहन भी आधा जल गया. दमकल अधिकारी के अनुसार आग का कारण पता नहीं चला. जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. दमकल विभाग को सुबह करीब 6.09 बजे आराधना नगर बस स्टॉप के पास के साहिल गैराज में आग लगने की सूचना मिली. ऐसे में वाठोड़ा दमकल केंद्र से 1 फायर टेंडर, 1 बाउजर व 1 छोटा फायर टेंडर भेजा गया. दमकलकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाकर आग पर काबू पाया. उसके बाद कूलिंग प्रक्रिया शुरु की गई. आग पर समय रहते काबू नहीं किया जाता तो आसपास की इमारतों को भी चपेट में ले लेता. दमकल विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार गैराज अनंत सुधाकर काले का है. आग में एमएच 47 वाई 9867 और एमएच 41 वाई 3646 जलकर खाक हो गई. जबकि गाड़ी क्रमांक एमएच 31 एफसी 5005 आधी और एमएच 31 सीक्यू 9047 क्रमांक की स्क्रैप हो चुकी गाड़ी आधी जली. दमकल विभाग ने 15 लाख रु. का नुकसान होने की बात कही है. वाठोड़ा दमकल केंद्र के अधिकारी चंद्रशेखर रणदिवे के नेतृत्व में आग पर काबू पाया गया. उधर, रघुजीनगर में संजय पाटिल की केक गैलरी नामक शॉप में बुधवार दोपहर 3.50 बजे आग लग गई. इससे 10 लाख रु का नुकसान होने का अंदेशा दमकल विभाग ने जताया है.

स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में उतरे गोंदिया के व्यापारी

उपभोक्ताओं की सहमति के बिना मीटर बदलने पर जताई आपत्ति

संवाददाता / गोंदिया

महावितरण द्वारा उपभोक्ताओं के वर्तमान बिजली मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने संबंधी भेजे जा रहे संदेशों को लेकर गोंदिया जिला व्यापारी एसोसिएशन (पंजीकृत) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन का कहना है कि उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया उचित नहीं है और इससे व्यापारी वर्ग सहित आम नागरिकों में चिंता एवं असंतोष का

वातावरण बन रहा है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि महावितरण द्वारा भेजे जा रहे संदेशों में कहीं भी उपभोक्ता की स्वीकृति या सहमति का उल्लेख नहीं किया गया है। उनका मानना है कि स्मार्ट मीटर जैसी व्यवस्था लागू करने से पहले उपभोक्ताओं को उसके लाभ, संभावित प्रभाव, शुल्क व्यवस्था और तकनीकी पहलुओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। संगठन ने मांग की है कि किसी भी उपभोक्ता का मौजूदा बिजली मीटर उसकी इच्छा के विरुद्ध न बदला जाए तथा स्मार्ट मीटर लगाने संबंधी सभी शासकीय निर्णय, अधिसूचनाएं और कानूनी प्रावधान सार्वजनिक किए जाएं।

साथ ही व्यापारी संगठनों, उपभोक्ता संगठनों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर पारदर्शी नीति अपनाई जाए। व्यापारी एसोसिएशन ने यह भी कहा कि जब तक उपभोक्ताओं की सभी शंकाओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक स्मार्ट मीटर योजना को पूर्णतः स्वैच्छिक रखा जाना चाहिए। संगठन ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, पालकमंत्री, संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों को विरोध पत्र भेजकर शीघ्र हस्तक्षेप की मांग करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो इसे उपभोक्ता अधिकारों का हनन मानते हुए लोकतांत्रिक एवं कानूनी माध्यमों से व्यापक विरोध किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष संजय जैन (लाडली), सचिव राजेश्वर कनोजिया तथा महासचिव राजा इसरका ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है।

आधा जून बीतने के बाद भी बारिश नहीं होने के लक्षण

संवाददाता / गोंदिया

मानसून में देरी से किसानों की आंखें आसमान पर लगी है. खरीफ की बुआई के लिए किसानों ने खेत तैयार कर रखे हैं. किसानों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है. मृग नक्षत्र की शुरुआत होते ही किसान खेतों में पहुंच गए. उन्होंने हल व बक्खर लेकर खेतों में काम भी शुरु कर तो दिया पर बारिश का इंतजार है. मान्यता है कि मृग नक्षत्र में की गई बुआई कभी बेकार नहीं जाती है और इसके लिए बरसात की जरूरत है. आधे से ज्यादा किसान हर साल मृग नक्षत्र में बुआई करते हैं जिससे समय पर फसल होती है, लेकिन इस वर्ष प्री मानसून के दूर-दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे है. जून का दूसरा पखवाड़ा समाप्त होने को आ रहा है. इसके बाद भी बारिश की शुरुआत नहीं होने से खरीफ की बुआई काम में देरी हो रही है.

लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है. जिससे बुआई का कार्य प्रभावित हो रहा है. किसानों के साथ ही आम नागरिकों को बारिश की प्रतीक्षा है. लेकिन इस वर्ष मानसून की देरी से किसानों की आंखे आसमान पर टिकी है.

सिंगल कॉलम फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज

संवाददाता / देवरी

राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित कॉम्पैक्ट ब्रिज के स्थान पर आधुनिक तकनीक से सिंगल कॉलम फ्लाईओवर के निर्माण की मांग को लेकर देवरी के नागरिकों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है. इसी क्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों व प्रतिनिधियों ने विधायक संजय पुराम से उनके पुराडा स्थित निवास पर मुलाकात कर मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि प्रस्तावित कॉम्पैक्ट ब्रिज के निर्माण से देवरी शहर दो हिस्सों में बंट तथा सकता है, जिससे स्थानीय व्यापार, यातायात

व्यवस्था शहर के समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. नागरिकों ने इसके बजाय सिंगल कॉलम फ्लाईओवर को मंजूरी देने की मांग की, जिससे सड़क के दोनों ओर पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहेगा और बाजार क्षेत्र भी प्रभावित नहीं होगा. नागरिकों का कहना है कि सिंगल कॉलम फ्लाईओवर आधुनिक शहरी ढांचे के अनुरुप है. इसके निर्माण से सड़क के दोनों ओर खुली जगह बनी रहेगी, जिससे स्थानीय दुकानदारों और व्यापारिक गतिविधियों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. साथ ही शहर की सुंदरता में वृद्धि होगी तथा यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी.

तिरोड़ा के खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में लहराया परचम, जीते स्वर्ण और रजत पदक

संवाददाता / तिरोडा

जिले में 12 से 14 जून 2026 के दौरान आयोजित वेस्ट जोन इक्विप्ड एवं क्लासिक पावरलिफ्टिंग, बेंच प्रेस तथा डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में तिरोड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि से तिरोड़ा के खेल जगत में खुशी और उत्साह का माहौल है। प्रतियोगिता में तिरोड़ा के प्रतिष्ठित आईएफसी जिम (आइकॉनिक फिटनेस सेंटर) के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत,

अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर प्रतियोगिता में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग स्पर्धा के सीनियर वर्ग के 85 किलोग्राम वजन समूह में शुभम मिश्राम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान शानदार तकनीक, आत्मविश्वास और शारीरिक क्षमता का परिचय देते हुए प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, जूनियर वर्ग के 69 किलोग्राम वजन समूह में तपिश टेमरे ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कड़े मुकाबले में द्वितीय स्थान हासिल कर रजत पदक जीता। तपिश की इस उपलब्धि को युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। दोनों खिलाड़ियों की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि तिरोड़ा के खिलाड़ी भी बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें बधाई दी है। आईएफसी जिम के संस्थापक सागर बावणकर ने खिलाड़ियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि निरंतर अभ्यास, समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने भविष्य में भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने का भरोसा जताया।

इस सफलता में आईएफसी जिम परिवार के सभी सदस्यों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के परिजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तिरोड़ा के नागरिकों ने आशा व्यक्त की है कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

साढ़े 3 माह में 16 लाख की तंबाकू जब्त

बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

संवाददाता / गोंदिया

गुटखा, तंबाकू और निकोटिन युक्त फसल का अवैध कारोबार कर करोड़ों रु. कमाने वाले तंबाकू माफियाओं के खिलाफ अब सीधे तौर पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लागू करने की तैयारी चल रही है. 1 मार्च से 15 जून तक साढ़े तीन महीनों में, खाद्य व औषधि प्रशासन ने जिले में छह छापे मारे हैं और 16 लाख रु. की तंबाकू जब्त की है. हालांकि, बार-बार कार्रवाई के बावजूद अवैध व्यापार रुकने का नाम नहीं ले रहे है.

इसलिए अब न केवल खुदरा विक्रेताओं बल्कि निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों, गोदाम संचालकों और वितरकों की पूरी श्रृंखला को मकोका के तहत लक्षित किया जाएगा. प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ क्षेत्रों में संगठित अवैध व्यापार देखा गया है.

जांच से पता चला कि नेटवर्क जाली दस्तावेजों, बेनामी लेनदेन, गुप्त गोदामों और अंतरराज्यीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से संचालित होता था. इस पृष्ठभूमि में, खाद्य व औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे ने गंभीर मामलों में मकोका लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. सिर्फ विक्रेता ही नहीं, पूरा नेटवर्क रडार पर प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार में शामिल पूरी चेन की जांच की जानी है. निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का निरीक्षण, ट्रांसपोर्टरों और गोदामों की जांच, पुलिस और एफडीए का संयुक्त अभियान चलाया जाएगा.

नवज्योत फाऊंडेशन के शिविर में ५१ यूनिट रक्त एकत्रित

संवाददाता / गोंदिया

नवज्योत फाऊंडेशन द्वारा होटल पैसिफिक में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया. उद्घाटन पार्षद बंटी पंचबुद्धे, एसआईपी अबैकस के डायरेक्टर मयूर त्रिवेदी, डॉ. अमित साबू तथा नवज्योत फाऊंडेशन की टीम के हाथों हुआ. शिविर में जीवन ज्योति ब्लड बैंक का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ. इस अवसर पर 51 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, विशेष रूप से महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर रक्तदान किया, जो समाज में बढ़ती जागरूकता और सहभागिता का प्रेरणादायक उदाहरण रहा. वहीं 28 लोगों ने अंगदान के लिए पंजीयन कर समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता और जागरूकता का परिचय दिया. रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र व स्मृति-चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया. अतिथियों ने अपने संबोधन में रक्तदान व अंगदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में इस पुनीत कार्य से जुड़ने का आव्हान किया.

२८ लोगों ने लिया अंगदान का संकल्प

विश्व रक्तदाता दिवस पर तिरोड़ा में आयोजित रक्तदान शिविर में ३२ लोगों ने किया रक्तदान

संवाददाता / तिरोड़ा

विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी सेवा अस्पताल, तिरोड़ा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 32 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। यह शिविर सोमवार, 15 जून को अस्पताल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अस्पताल प्रशासन की ओर से बीमित मरीजों की सेवा और जनस्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आयोजित रक्तदान शिविर में नागपुर स्थित हेडगेवार रक्तपेढ़ी की टीम ने रक्त संकलन का कार्य किया। शिविर का आयोजन बीमा चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्णकांत चाटे एवं डॉ. राहुल पाटील के मार्गदर्शन में किया गया।

इस दौरान अधीपरिचारिका भाग्यश्री क्षिरसागर, कृपाली नंदेश्वर तथा सुशांत वासनिक की उपस्थिति में विशेषज्ञों द्वारा सभी आवश्यक नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए रक्त संकलित किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 61 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी प्रतिभागियों की रक्त जांच के साथ-साथ रक्तचाप, शुगर, सिकल सेल तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण किए गए। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत 32 योग्य व्यक्तियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने

बताया कि रक्तदान मानव सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है।

सिकल सेल, थैलेसीमिया जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों को नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रसूति के मामलों, गंभीर बीमारियों तथा सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के उपचार के लिए भी रक्त अत्यंत आवश्यक होता है। रक्तदान से किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। शिविर के दौरान सभी रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र, डोनर कार्ड एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में भाग्यश्री केळवतकर, कृपाली नंदेश्वर, सुशांत वासनिक, विनय शरणागत, अनुराग गोंडाणे, संस्कृति मेश्राम, देवेंद्र डहारे, अतुल गोले, स्वरूप लिल्हारे तथा प्रविणा वालदे सहित अस्पताल के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राज्यस्तरीय सांडा वुशू जज एवं रेफरी परीक्षा में चंद्रप्रकाश प्रजापती

अमन नंदेश्वर एवं राजेश वरठे ने प्राप्त किया 'ए' ग्रेड

संवाददाता / तिरोडा

ऑल महाराष्ट्र वुशू एसोसिएशन की मान्यता तथा अहमदनगर जिला एमेच्योर वुशू एसोसिएशन के तत्वावधान में शिर्डी स्थित साई पालखी निवारा, निमगांव में १२ से १५ जून २०२६ तक राज्यस्तरीय वुशू जज एवं रेफरी प्रशिक्षण एवं प्रमाणन पाठ्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। चार दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में महाराष्ट्र के २५ जिलों से कुल १४६ रेफरी, जज, प्रशिक्षकों एवं खेल अधिकारियों ने सहभागिता कर अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल का विकास किया। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य वुशू खेल से जुड़े जजों, रेफरियों एवं प्रशिक्षकों को नवीनतम नियमों, तकनीकी मानकों तथा प्रतियोगिता संचालन की आधुनिक पद्धतियों से अवगत कराना था। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को वुशू खेल की अद्यतन नियमावली, रेफरी के तकनीकी दायित्व, प्रतियोगिताओं के संचालन की प्रक्रिया, अंक प्रणाली, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू नवीन नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही ताओलू (Taolu) एवं सांडा (Sanda) स्पर्धाओं की तकनीकी बारीकियों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं राष्ट्रीय रेफरी, एसजीएफआई तथा एनआईएस प्रशिक्षक लक्ष्मण उदमले, दिनेश माली, अविनाश पाटिल एवं दीपक भिसेन ने मुख्य प्रशिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। इनके अतिरिक्त पांडुरंग अंभोरे, आनंद भुसारी, विजयकुमार खंडार, महेश इंदापुरे, सुरेश चौधरी, अनिल खराडे, दत्तात्रेय पाटिल एवं उत्तम उगाडे ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस राज्यस्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम में गोंदिया जिला वुशू एसोसिएशन के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजित जज एवं रेफरी परीक्षा में गोंदिया जिले के चंद्रप्रकाश प्रजापती, अमन नंदेश्वर एवं राजेश वरठे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 'ए' ग्रेड प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से गोंदिया जिले का नाम राज्य स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

इस सफलता पर तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजयभाऊ रहांगडाले, नगर परिषद तिरोड़ा के अध्यक्ष अशोक असाटी, उपाध्यक्ष राजेश गुन्हेरिया, विजय बनसोड, जिला क्रीड़ा अधिकारी भोजराज चौधरी, तालुका क्रीड़ा अधिकारी अभय महल्ले, अधिवक्ता माधुरी रहांगडाले सहित अनेक खेलप्रेमियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सभी सफल प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। वहीं मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एंड हेल्पिंग ग्रुप, तिरोड़ा तथा क्षेत्र के खेलप्रेमियों ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों से प्रशिक्षकों एवं रेफरियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी तथा भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी, प्रशिक्षक और रेफरी तैयार करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। गोंदिया जिले के प्रतिभागियों की यह सफलता जिले के खेल विकास के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि मानी जा रही है।

जाहिर सुचना

श्रीमती हिराबाई राधेश्याम अग्रवाल इनके नाम से नगर परिषद रिकार्ड में नाम दर्ज है. जिसका वार्ड क्रमांक 10/491,492,493 वार्ड का नाम शास्त्री वार्ड वार्ड है. उक्त मालमत्ता धारक का निधन दिनांक :- 06/05/2021 को हो चुका है. इनके निधन उपरांत इनके वारस 1) सीताराम राधेश्याम अग्रवाल, 2) राजेश राधेश्याम अग्रवाल इन्होने वारसान आधार पर हस्तांतरण हेतु आवेदन सादर किया है. हस्तांतरण पर आक्षेप हो तो यह सुचना प्रकाशित होने के पश्चात 15 दिन के भितर अपना आक्षेप इस कार्यालय में प्रमाणित दस्तावेज सहित सादर करेंगे. आक्षेप प्राप्त न होने पर हस्तांतरण की कार्यवाही की जायेगी.

मुख्य अधिकारी
नगर परिषद गोंदिया

गोंदिया वनविभागातील वनोपजाचा मैदानी लिलाव सुचना

उपवनसंरक्षक प्रा. गोंदिया वनविभाग, गोंदिया यांचे अखत्यारित असलेल्या चिचगड येथील शासकिय विक्री आगारात खालील प्रमाणे मालाचा मैदानी लिलाव आयोजित करण्यात येत आहे. तरी इच्छुक खरेदिदारांनी खालील नमुद दिवशी विक्री आगारात हजर राहण्याचे आवाहन याद्वारे करण्यात येत आहे.

आगार चे नाव	लिलावाचा दिनांक	लिलाव ची वेळ	मालाचा प्रकार	ईमारत घ.मी.	जळाऊ भर	फाटे
चिचगड	23/06/2026 मंगळवार	सकाळी 11.00 ते सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंत	साग	2.200	0.00	0
			सागेत्तर	16.541	0.00	0
			एकुण	18.741	00.00	00

महत्वाची सुचना :- मैदानी लिलावात लावण्यात येणारा माल हा वरिलप्रमाणे अंदाजित दाखविण्यात आला आहे. सदर मालात कमी अधिक पणा करण्याचे तसेच लिलावाच्या वेळेवर माल कमी वा अधिक करण्याचे अधिकार निम्नस्वाक्षरीकर्ता यांचेकडे राखुन ठेवण्यात येत आहे. तसेच, सदर मालाची मटेरियल लिस्ट ही संबंधित आगाराकडुन प्राप्त करुन घेऊन माल आगारात लिलावापुर्वी पाहुन घ्यावा. अधिक माहिती करिता उक्त आगार कार्यालयाशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

स्वा/-
(पवनकुमार आ.जोंग)
उपवनसंरक्षक
गोंदिया वनविभाग, गोंदिया

क्र.संमावज/नाग/१६९/२०२६

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरूनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरूनानक वार्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.
संपादक :- चंद्रकात खंडेलवाल, पी.आर.पी एक्ट के तहत जिम्मेदार *